

खरीफ फसल की वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगा उत्पादन, किसानों को बताए उन्नत तकनीक के गुर

नावकोठी, संवाददाता, अमित कुमार

ई-किसान भवन नावकोठी के सभागार में कृषि विभाग के तत्वावधान में खरीफ फसल उत्पादन तकनीक को लेकर किसान गोष्ठी सह जागरूकता बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रखंड क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से पहुंचे किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। कृषि कर्मियों ने किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। बैठक में बीटीएम विवेकानंद सिंह ने धान, मक्का, अरहर, सोयाबीन एवं सब्जियों सहित अन्य खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेहतर उत्पादन के लिए खेत की उचित तैयारी, गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन, समय पर बुआई व रोपाई,



संतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग तथा फसल की नियमित निगरानी जरूरी है। किसानों को मौसम एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार कृषि कार्य करने की सलाह दी गई। एसएमएस शिवचंद्र कुमार ने कृषि विभाग एवं सरकार की ओर से संचालित किसान हितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ लेने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में

बताया। उन्होंने जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट तथा जैव-इनपुट के उपयोग पर जोर दिया। कृषि समन्वयक सुरेंद्र कुमार ने प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज के चयन, बीज उपचार और निर्धारित मात्रा में बीज प्रयोग की जानकारी दी। वहीं गौतम गोस्वामी ने कीट प्रबंधन एवं फसल सुरक्षा के

उपाय बताए। उन्होंने अनावश्यक रासायनिक कीटनाशकों से बचने और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाने की सलाह दी। मौके पर किसान सलाहकार अजीत, पंकज पोद्दार, सुनील कुमार श्रवण कुमार, पंचायत समिति गौतम गोस्वामी, अरविंद पासवान सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कृषि विभाग के कर्मी मौजूद थे।

सही पोषण, देश रौशन के संदेश से गूंजा आंगनबाड़ी केंद्र



नावकोठी, संवाददाता, अमित कुमार

महेशवाड़ा पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-07 पर बुधवार को ह्रसही पोषण, देश रौशनक के संदेश के साथ पोषण माह का आगाज किया गया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं, धातु माताओं, किशोरियों तथा दो वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से बचाव के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीडीपीओ गुंजन मौली ने कहा कि सही पोषण के माध्यम से ही कुपोषण पर प्रभावी ढंग से जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं से अपने-अपने पोषक क्षेत्र के सभी पात्र लाभुकों तक पोषण संबंधी संदेश पहुंचाने तथा अभियान को जन-जन तक ले जाने की अपील की। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अनाज, फल तथा आयरन-फोलिक एसिड आदि से आकर्षक रंगोली बनाकर पोषण जागरूकता का संदेश

दिया गया। पोषण संवाद के माध्यम से संतुलित आहार और भोजन में मोटे अनाज के उपयोग से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों की वृद्धि एवं विकास की निगरानी, एनीमिया से बचाव तथा भोजन में रागी जैसे पोषक मोटे अनाज को शामिल करने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि बच्चों को जन्म से दो वर्ष तक पर्याप्त एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने से उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास को मजबूती मिलती है।

वहीं गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव तथा आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों के नियमित सेवन के महत्व से अवगत कराया गया। महिलाओं को भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करने के लिए भी प्रेरित किया गया। मौके पर एलएस शालिनी, कृष्णा, सुनीता, पुनम, सेविका कोमल, प्रमिला, रंजना, शीला, सीमा एवं कंचन, एएनएम सोनी, आशा कार्यकर्ता वंदना सहित पोषक क्षेत्र के लाभुक मौजूद थे।

दिनकर की मूर्ति स्थापना की मांग को लेकर पूर्व मंत्री विधायक एवं विधान पार्षद से मिले प्रतिनिधि मंडल

वरिष्ठ संवाददाता/ महंत रामजीवन दास

वरौनी/बेगूसराय। सिमरिया सिक्स लेन गोलंबर पर दिनकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर गुरुवार को सिमरिया के बुद्धिजीवियों ने विधान पार्षद सर्वेश कुमार, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता एवं मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह से भेंट की। राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति स्थापना संघर्ष समिति के सहसंयोजक कृष्ण मुरारी ने बताया कि छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सिमरिया सिक्स लेन गोलंबर पर दिनकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई। विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि को साहित्यिक तीर्थ भूमि बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अनेक विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि हम आपकी मांग का समर्थन करते हैं। सरकार तक इन बातों को पहुंचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। पूर्व मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि दिनकर की जन्मभूमि पर राष्ट्रकवि दिनकर की मूर्ति ही स्थापित होगी। सरकार इसे अपने एजेंडे में ले चुकी है। हम सब इस ओर प्रयासरत हैं।



● राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि को साहित्यिक कृष्ण भूमि बनाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है विधान पार्षद सर्वेश कुमार

● दिनकर की जन्मभूमि पर दिनकर की प्रतिमा ही स्थापित होगी। सरकार ने इसे अपने एजेंट में ले चुकी है और हम सब भी प्रयासरत रहते हैं : सुरेंद्र मेहता पूर्व मंत्री

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों को अपना मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विश्वम्भर सिंह, कैलाश

सिंह, गुलशन कुमार, पंकज कुमार एवं मीडिया प्रभारी संजीव फिरोज शामिल थे। मीडिया प्रभारी ने कहा कि जब तक दिनकर

की मूर्ति नहीं लगेगी ,तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हम प्रशासन एवं सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं।

बिहार: एक-दूसरे को डूबने से बचाने के प्रयास में 5 की मौत, मरने वालों में एक ही परिवार के 4 सदस्य

पुराने रेल मार्ग से कुशेश्वरस्थान तक रेल परियोजना पूरी कराने की मांग, हरनगर स्टेशन पर धरना

दरभंगा, सं। दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान क्षेत्र में सकरी-हसनपुर रेल परियोजना को पुराने मार्ग से ही कुशेश्वरस्थान तक पूरा कराने की मांग को लेकर गुरुवार को हरनगर स्टेशन परिसर में कुशेश्वरस्थानधाम रेल परियोजना निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मधुकांत झा मिंटू की अध्यक्षता में आयोजित धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भाग लिया। धरने को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता शंकर कुमार झा ने कहा कि हरनगर से कुशेश्वरस्थान तक पुराने रेल रुट को छोड़कर नया मार्ग बनाने की प्रक्रिया किसानों के साथ अन्याय और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने वाली होगी। उन्होंने कहा कि पुराने रुट पर करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में 90 प्रतिशत मिट्टी कार्य के साथ पुल-पुलिया का निर्माण भी हो चुका है।

भागलपुर, संवाददाता। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। गुरुवार को बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में बाढ़ के गहरे पानी में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातमी सनटा पसरा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, पीड़ित परिवार के सदस्य अपने खेत की ओर जा रहे थे। बाढ़ के कारण सड़क पूरी तरह जलमग्न थी। इसी दौरान पैर फिसलने या गहराई का अंदाजा न मिलने के कारण परिवार का एक सदस्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी लोग भी एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर पानी में उतर गए। देखते ही देखते, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में पांचों लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए तत्परता दिखाई और भारी मशक्कत के बाद सभी को पानी से बाहर निकाला। आनन-फानन में सभी



को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पांचों लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में मंचों देवी, सोनाक्षी कुमारी, प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार और अंशु प्रिया के रूप में की गई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। एक साथ पांच शवों के अस्पताल पहुंचते ही

परिजनों के करुण क्रंदन से पूरा अस्पताल परिसर गूंज उठा। घटना की जानकारी मिलते ही बाईपास थाना पुलिस बल के साथ मायागंज अस्पताल पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय पंचायत के मुखिया और थानाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सात्वना दी। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और जुझारू है। लोगों का कहना है कि

सड़कों पर बाढ़ का पानी जमा होने के कारण गह्वों और नालों की गहराई का पता नहीं चल पा रहा है, जिससे लगातार हादसे की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी जलजमाव वाले और खतरनाक स्थानों पर तुरंत बैरिकेडिंग की जाए, सुरक्षाकर्मियों की तैनाती हो और लोगों को सतर्क करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।

मिलती है और दत्तक माता-पिता को भी भविष्य में किसी तरह की कानूनी परेशानी नहीं होती। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के दौरान प्रभारी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई रूपेश कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी सुधीर कुमार गोंड, प्रभारी समन्वयक वंदना प्रिया सहित संबंधित अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। बच्चों के नए परिवार से जुड़ने के मौके पर संस्थान में खुशी का माहौल रहा।

सीवान के तीन बच्चों को मिला नया परिवार, तमिलनाडु, गोवा और झारखंड के दंपतियों ने लिया गोद

सीवान, संवाददाता। सीवान के तीन बच्चों के जीवन में शुक्रवार को नई उम्मीद और खुशियों का आगाज हुआ। दत्तक ग्रहण नियमावली, 2022 के प्रावधानों के तहत जिला पदाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं बालगृह में आवासित तीन बच्चों को उनके नए माता-पिता को सौंपने के लिए अंतिम दत्तक ग्रहण आदेश पारित किया। इनमें दो बालिकाओं को तमिलनाडु

और गोवा के दंपतियों तथा करीब आठ वर्षों से बालगृह में रह रहे एक बालक को झारखंड के दंपति ने गोद लिया। प्रशासन के अनुसार, बच्चों को करीब दो माह पूर्व ही उनके भावी दत्तक माता-पिता को ह्यप्री एडॉप्शन फोस्टर केयरहू के तहत सौंप दिया गया था। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी ने दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश पारित किया। इसके साथ ही तीनों बच्चों को

कानूनी रूप से उनके नए परिवार का हिस्सा बनने का रास्ता साफ हो गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि किसी भी अनाथ, परित्यक्त या फेके हुए बच्चे को अवैध तरीके से गोद न लें। यदि कहीं कोई ऐसा बच्चा मिलता है तो उसे अपने स्तर से

किसी व्यक्ति को सौंपने के बजाय जिला बाल संरक्षण इकाई, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, नजदीकी थाना अथवा चार्ल्ड हेल्थलाइन नंबर 1098 के माध्यम से सुरक्षित व्यवस्था तक पहुंचायें। उन्होंने कहा कि निःसंतान दंपति यदि किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेना चाहते हैं तो केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अधिकरण के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे बच्चे को भी कानूनी सुरक्षा



एक नजर

बंदोबस्ती की जमीन पर कब्जे का आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग

किशनगंज, संवाददाता।

कोचाधामन थाना क्षेत्र के पाटकोई खुर्द निवासी करीब 65 वर्षीय अकालू लाल हरिजन ने सरकारी बंदोबस्ती की जमीन पर दबंगों द्वारा कथित रूप से कब्जा करने, रंगदारी मांगने, मारपीट एवं धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में अकालू लाल ने बताया है कि बिहार सरकार से बंदोबस्ती के माध्यम से उन्हें मौजा पाटकोई कला, थाना नंबर 21, खता नंबर 237, बेसरा नंबर 2264 में दो एकड़ जमीन मिली है। उक्त जमीन से उनका परिवार खेती-बाड़ी और जीविकोपार्जन करता है। आरोप है कि विनोद कुमार, दिलीप कुमार, विकास कुमार, दिलीप, अरुण, सहदेव

और कमलेश उर्फ कलस ने कथित रूप से मिलकर जमीन पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और उन्हें वहां से बेदखल कर दिया। आवेदक का आरोप है कि आरोपित उन्हें जमीन पर जाने और खेती करने नहीं देते हैं। जमीन वापस करने अथवा वहां जाने देने के नाम पर बार-बार रुपये की मांग की जाती है। भय और दबाव में कई बार रुपये देने के बावजूद जमीन वापस नहीं किए जाने की बात आवेदन में कही गई है। साथ ही गाली-गलौज, मारपीट और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि नामजद आरोपितों में शामिल दिलीप कुमार ग्रामीण पुलिस चौकीदार के पद पर कार्यरत है और कथित रूप से अपने पद एवं वर्दी का प्रभाव दिखाकर आवेदक और उसके परिवार को धमकाता है।

भूमि व गंडक घाट विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, पांच घायल

बेतिया, संवाददाता। बेतिया पुलिस जिला स्थित नौतन थाना क्षेत्र के बरदाहां पंचायत के वार्ड संख्या 13 में पूर्व के भूमि विवाद और गंडक नदी के घाट पर शराब पार कराने को लेकर गुरुवार की अहले सुबह हुए विवाद में मुकेश यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट की घटना में पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में चल रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मडुआहां निवासी गजेंद्र यादव और बनहौरा



निवासी मुकुंद यादव को हिरासत में लेकर पृच्छाछ शुरू कर दी है। मृतक के भाई बलिंद्र यादव के बयान पर पुलिस ने ग्यारह लोगों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज किया है।

पीड़ित ने बताया कि भूमि विवाद और गंडक नदी के घाट को लेकर

पूर्व से चले आ रहे विवाद ने गुरुवार की सुबह उस समय गंभीर रूप ले लिया। जब दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान मुकेश यादव पच्चीस वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही

उनकी मौत हो गई। वहीं पांच अन्य लोग भी घायल हो गए।

प्राथमिकी के आधार पर पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।इधर युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

परिजन आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहां एसडीपीओ राकेश कुमार भास्कर पहुंचकर परिवार के लोगों की बात कही। थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान के नेतृत्व में पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है।

सम्मानित किए गए वरिष्ठ नागरिक

कटिहार, संवाददाता। केंद्र प्रायोजित 'अटल वयो अभ्युदय योजना' की उप-योजना एसएपीएससी की राज्य कार्य योजना के तहत गुस्वार को जिले के कटिहार सदर, मनिहारी और बारसोई स्थित बुनियाद केंद्रों में अंतर-पीढ़ीगत तालमेल गतिविधि का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नई और पुरानी पीढ़ी के बीच आपसी समझ व सम्मान को मजबूत करना और वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों व कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना था। सदर बुनियाद केंद्र में सहायक निदेशक यशस्वी ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आयोजन के दौरान दोनों पीढ़ियों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए कौशल, पारंपरिक कला-शिल्प व ज्ञान के आदान-प्रदान के साथ संवाद श्रृंखला, पेंटिंग, ड्राइंग और कहानी-कविता पाठ जैसी रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं।

किसानी को लेकर किसानों का रुझान बढ़ा है।

मक्का आधारित उद्योग धंधे स्थापित होने से किसानों को काफी लाभ मिलेगा। वहीं बंद पड़े और बंद के राह पर स्थापित उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने पर भी उद्यमी आयोग के सदस्य ने ध्यान अकृष्ट कराया।

उद्यमी आयोग के सदस्य ने सीएम से की मुलाकात सीमांचल के समस्याओं के निराकरण पर की चर्चा

अररिया, संवाददाता। बिहार राज्य उद्यमी आयोग के सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता आलोक भगत उर्फ बमशंकर भगत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना में गुरुवार को मुलाकात कर अररिया सहित सीमांचल से जुड़े उद्योग धंधे सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की और उसके निराकरण को लेकर सकारात्मक प्रयास करने की विनती की।

जागरुकी देते हुए श्री भगत ने बताया कि सीमांचल में उद्योग धंधे स्थापित करने खासकर खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग स्थापित करने,किसानों की समस्याओं के तहत सरकारी रेट पर यूरिया और डीपीए उपलब्धता पर चर्चा की।साथ ही नरपतगंज बाजार में फोरलेन सड़क पर अंडर पास में होने वाले



जलजमाव की समस्या पर निराकरण के लिए एनएचआई से पहल करने की मांग की।इसके अलावा बॉर्डर सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रकोप और तस्करी जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की गई।

श्री भगत ने सीएम को बताया कि अररिया और सीमांचल में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं।खासकर जिस तरह से कुछ वर्षों में मक्का के उत्पादन और

जलजमाव की समस्या पर निराकरण के लिए एनएचआई से पहल करने की मांग की।इसके अलावा बॉर्डर सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रकोप और तस्करी जैसे मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की गई।

श्री भगत ने सीएम को बताया कि अररिया और सीमांचल में उद्योग धंधों की अपार संभावनाएं हैं।खासकर जिस तरह से कुछ वर्षों में मक्का के उत्पादन और

सड़क किनारे प्लेसेंटा और मृत भ्रूण फेंके जाने की सूचना पर नर्सिंग होम में छापेमारी

सुपौल, संवाददाता। जिले में राघोपुर प्रखंड के सिमराही नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे प्लेसेंटा और कथित तौर पर मृत भ्रूण फेंके जाने की सूचना के बाद प्रशासन ने गुरुवार को ओम सत्य नर्सिंग होम में छापेमारी की। कार्रवाई वीरपुर एसडीएम विनय कुमार के नेतृत्व में की गई। प्रशासनिक टीम ने नर्सिंग होम पहुंचकर मेडिकल वेस्ट के निस्तारण से संबंधित दस्तावेज, व्यवस्था और संस्थान के संचालन से जुड़े नियमों की जानकारी ली। टीम ने मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया, संबंधित रिकॉर्ड और निर्धारित नियमों के अनुपालन की भी जांच की।

छापेमारी के दौरान नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली, रेफरल अस्पताल राघोपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.



दीप नारायण राम, राघोपुर थाना के एसआई पुष्पांजय कुमार सहित पुलिस बल मौजूद रहा। जांच टीम ने नर्सिंग होम में मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान कुछ मरीज भी मिले, जिनका ऑपरेशन हुआ था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संस्थान में इलाज और मेडिकल वेस्ट प्रबंधन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की।

रेफरल अस्पताल राघोपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीप नारायण राम ने बताया कि सड़क किनारे प्लेसेंटा फेंके जाने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि बायो-मेडिकल वेस्ट का निस्तारण निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाना जरूरी है। प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर अनियमितता से जुड़ा हो सकता है। जांच पूरी होने के

बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली ने बताया कि सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से नर्सिंग होम की जांच की। मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों को संचालित किया जा रहा है। वीरपुर एसडीएम विनय कुमार ने कहा कि मेडिकल वेस्ट के साथ मृत भ्रूण फेंके जाने की सूचना मिली थी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ओम सत्य नर्सिंग होम के संचालन की वैधानिकता की भी जांच कराई जाएगी। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक या जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

प्रादेशिक

विद्युत आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा : ऊर्जा मंत्री

बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा सम्मेलन में बिहार बना राज्य सहभागी



नई दिल्ली/पटना, संवाददाता। बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित 19वें पर्यावरण एवं ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार की ग्रामीण विद्युतीकरण यात्रा विषय पर संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने बिहार के विद्युत क्षेत्र में हुए व्यापक बदलाव तथा ऊर्जा सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी देश के लिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित करना आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे सम्मेलन बिहार को विद्युत क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों

है कि निरंतर निवेश, मजबूत इच्छाशक्ति और प्रभावी नीतियों के माध्यम से व्यापक बदलाव संभव है। कभी बुनियादी विद्युत पहुंच की चुनौतियों से जुझने वाले बिहार ने आज हर घर और हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित कर ली

है। ऊर्जा सुरक्षा हमारे लिए केवल तकनीकी लक्ष्य नहीं, बल्कि बिहार की विकास यात्रा की मजबूत नींव है। हम निवेशकों और उद्योग जगत के भागीदारों को बिहार की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्र में व्यापक निवेश किया गया है। राज्य में विद्युत ग्रिड, उपकेंद्रों एवं पारेषण लाइनों के विस्तार के साथ विद्युत आधारभूत संरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 9,475 मेगावाट की अधिकतम विद्युत मांग तक पहुंच चुके बिहार में बढ़ती मांग को पूरा करने तथा राज्य

भागलपुर के 2.92 लाख पेंशनधारियों के खातों में 33.67 करोड़ रुपये का अंतरण

भागलपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर भागलपुर जिले के 2,92,094 पेंशनधारियों के बैंक खातों में माह अगस्त, 2026 की कुल 33 करोड़ 67 लाख 64 हजार 900 रुपये की पेंशन राशि सीधे हस्तांतरित की गई। पेंशन राशि में हुई इस वृद्धि से जिले के वृद्धजन, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों में उत्साह एवं खुशी का माहौल देखा गया। राज्य सरकार द्वारा इस विशेष अवसर को पेंशन उत्सव के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सम्मान, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक संबल प्रदान करने का संदेश देना है। भागलपुर समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त रवि राकेश सहित कई वर्यय पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी उपस्थित रहे।

बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन, 35 प्रशिक्षुओं ने लिया प्रशिक्षण

सुगौल, संवाददाता। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), मरिचा में आयोजित 12 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समापन नगर परिषद के पार्षद बबलू कुमार ने किया। प्रशिक्षण में कुल 35 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक टी.एस. केर-केट्टा ने प्रशिक्षुओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त जानकारी का उपयोग कर युवा एवं अन्य प्रशिक्षु बकरी पालन को रोजगार का जरिया बना सकते हैं। स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने जीवन स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम संचालक सह फैकल्टी मुकेश कुमार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ अपने जीवन स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम संचालक सह फैकल्टी मुकेश कुमार मुस्कान ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण उपरांत मिलने वाले लाभ एवं स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दी।

सुरहा धार में मिला युवक का शव, शिनाख्त हुई

अररिया, संवाददाता। फारबिसगंज थाना क्षेत्र के खैरखा पंचायत स्थित खैरखा समीप पथ में सुरहा धार में पुल के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया। शव को देखने सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने शव की पहचान खैरखा पंचायत के बोचाभाग वार्ड संख्या पांच निवासी अभिषेक कुमार सिंह पिता स्व.उमेश सिंह के रूप में की है। उनकी उम्र लगभग 25 वर्ष की होगी।

पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटनास्थल पर मौजूद पंचायत के सरपंच संतोष कुमार सिंह एवं स्थानीय ग्रामीण श्यामकिशोर सिंह ने बताया कि मृतक फारबिसगंज के टीभीएस शो रूम में कार्यरत था तथा



मंगलवार को घर से दिन में फारबिसगंज शो रूम जाने के लिए अपने काम पर निकल था। शाम को घर नहीं पहुंचने पर रात में स्वजनों एवं ग्रामीणों द्वारा काफी खोजबीन की गई। लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया।

ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर को सुरहा धार पुल के नीचे एक शव पानी में पड़ा है। इस हो हल्ला पर सैकड़ों की संख्या में पुल के पास लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ में

लोगों ने शव की पहचान अभिषेक के रूप में की।

लोगों ने बताया कि युवक का बाएक गायब है।सूचना पर फारबिसगंज थाना के एसआई विजय कुमार सदलबल पहुंच कर मामले की जांच पड़ताल कर शव को अपने कब्जे में लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने बताया कि शव की पहचान हो गई है। शव के दोनों घुटने एवं मुंह में चोट के निशान है। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।स्थानीय लोगों ने बताया की मृतक अविवाहित था। अपने घर का इकलौता चिराग था। अपने नज्द माता का भरण पोषण करता था।सरपंच ने बताया कि इनकी पिता की मृत्यु चार पांच माह पूर्व हुई है। घर में सिर्फ एक मां है।

परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति का सच फिर सामने आया, लालू परिवार पर आरोप तय : संजय सरावगी



चाहिए कि उसके बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले बार-बार क्यों सामने आते रहे हैं। सरावगी ने कहा कि राजद के पास बिहार की जनता के सामने बताने के लिए विकास का मॉडल नहीं है। उसके पास सिर्फ परिवारवाद, जातिवाद और सत्ता के कथित दुरुपयोग की राजनीति का इतिहास है।

उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि जब आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े मामले अदालत में हैं, तो हर जांच और हर न्यायिक कार्रवाई को राजनीतिक प्रशिक्षण बताकर बच निकलने की कोशिश क्यों की जाती है?

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब सब देख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ राजद आज भी अपने पुराने राजनीतिक तौर-तरीकों से बाहर नहीं निकल पाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि न्यायपालिका अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और अब राजद को भी कानून की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए जांच और ट्रायल का सामना करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजद को परिवार बचाने की राजनीति छोड़कर बिहार के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बिहार की जनता अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद नहीं, विकास और सुशासन चाहती है।

सुपौल के 2.63 लाख लाभार्थियों को मिले पेंशन राशि के 28.80 करोड़ रुपये

सुगौल, संवाददाता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के 1,05,67,975 लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। प्रत्येक लाभार्थी को 1100 रुपये की पेंशन राशि दी गई। इस दौरान राज्यभर के लाभार्थियों के खातों में कुल 12,33,86,79,800 रुपये का अंतरण किया गया। इसी क्रम में सुगौल जिले के 2,63,342 लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 28,80,93,200 रुपये की पेंशन राशि भेजी गई। जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 1,72,308 लाभार्थियों को 20,32,93,200 रुपये, इंदिरा गांधी



राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 49,535 लाभार्थियों को 5,46,28,500 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 11,752 लाभार्थियों को 1,33,83,400 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 13,781 लाभार्थियों को 1,53,68,200 रुपये, बिहार निश्चिन्ता पेंशन योजना के 15,169 लाभार्थियों को 1,69,09,700 रुपये तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निश्चिन्ता

पेंशन योजना के 797 लाभार्थियों को 8,76,700 रुपये की राशि अंतरित की गई। पेंशन राशि के डीबीटी के माध्यम से अंतरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखने के लिए सुगौल जिला मुख्यालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 100 से अधिक निश्चिन्ता पेंशन योजना के अलावा पदाधिकारी सावन कुमार सहित विभिन्न जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।

मनमानी पर अदालत की चोट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किये जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के रवैये पर जो सख्त टिप्पणियां की हैं, वे देश की सभी राज्य सरकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए गंभीर चेतावनी हैं। अदालत ने अधिकारियों के रवैये को तानाशाहीपूर्ण बताते हुए यह स्पष्ट किया कि सरकारी शक्ति का इस्तेमाल किसी नागरिक की स्वतंत्रता को मनमाने ढंग से छीनने के लिए नहीं किया जा सकता।

अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत छात्रा की हिरासत रद्द करते हुए साफ संकेत दिया है कि असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल सामान्य मामलों में नहीं किया जा सकता। एहतियाती हिरासत एक असाधारण उपाय है और इसे तभी उचित ठहराया जा सकता है, जब संबंधित व्यक्ति से सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तविक और गंभीर खतरा होने के ठोस एवं विश्वसनीय प्रमाण मौजूद हों। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे कठोर प्रावधान सामान्य आपराधिक कानून का आसान विकल्प नहीं हो सकते। इनका इस्तेमाल असहमति की आवाज दबाने या लोकतांत्रिक विरोध को कुचलने के लिए भी नहीं होना चाहिए। इस मामले में पुलिस अदालत के समक्ष ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिससे छात्रा का हिंसा भड़काने से सीधा संबंध साबित हो सके। न तो पर्याप्त व्हाट्सएप संदेश, न वीडियो और न ही ऐसा अन्य प्रमाण सामने आया, जिससे यह सिद्ध हो कि उसने लोगों को दंगे या तोड़फोड़ के लिए उकसाया था। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने हिरासत को रद्द कर दिया। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी शालीपूर्ण विरोध और अपनी बात रखने के अधिकार की ताकत का गवाह रहा है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का अधिकार देता है। हालांकि, विरोध के अधिकार और हिंसा भड़काने के कृत्य के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना जरूरी है। हिंसा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से कानून के अनुसार सख्ती से निबट्टा जाना चाहिए। लेकिन केवल असहमति को अपराध मानकर कठोर कानून लगा देना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। मामले में एक गंभीर पहलू गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के समय और अधिकारिक रिकॉर्ड तैयार किये जाने के दौरान सामने आई विसंगतियों पर भी सवाल उठाये। सबसे अधिक की टिप्पणी से यह संकेत मिलता है कि कार्रवाई को बाद में सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड तैयार किये जाने की आशंका थी। किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने की कार्रवाई में प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी प्रावधानों का पालन सर्वोच्च महत्व रखता है। अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों से पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूलने तथा उनके सेवा रिकॉर्ड में इस कार्रवाई से संबंधित टिप्पणी दूज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला सरकारी अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकारी शक्ति के दुरुपयोग की कीमत हमेशा सरकारी खजाने से ही नहीं चुकायी जानी चाहिए। अधिकारी सरकारी शक्ति के मालिक नहीं, बल्कि संविधान और कानून के संरक्षक हैं। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है। सरकार की आलोचना या विरोध को व्यवस्था के लिए खतरा मान लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राजनीतिक दबाव में कानून की सीमाओं की अन्देखी करने वाली प्रशासनिक व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता के लिए नुकसानदेह है। कठोर कानून लगाने से पहले उसकी आवश्यकता, औचित्य और कानूनी आधार की पूरी तरह जांच करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां यही संदेश देती हैं कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर नागरिक अधिकारों का मनमाना हनन स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकारी पद किसी अधिकारी को असीमित अधिकार नहीं देता। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम जवाबदेही संविधान और कानून के प्रति होती है। इसलिए असाधारण कानूनों के इस्तेमाल में पारदर्शिता, विवेक और व्यक्तिगत जवाबदेही सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।



डॉ रीता सिंह

बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर लंबे समय तक गरीबी, सीमित रोजगार अवसर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और महिलाओं की कम आर्थिक भागीदारी के वर्णम से देखी जाती रही है। लेकिन, बिहार के उन्ही गांवों में एक ऐसी आर्थिक कहानी भी आकार ले रही है, जिसे केवल महिला सशक्तीकरण की उपलब्धि कहकर छोड़ देना उसके व्यापक महत्व को कम करके आंकना होगा।

जीविका दीदियों द्वारा बच्चों के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी की ड्रेस तैयार करने का काम इसी बदलती तस्वीर का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कहानी सिलाई मशीन से शुरू होकर रोजगार, सरकारी खरीद, स्थानीय उत्पादन, महिला नेतृत्व और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी के पुनर्संचार तक पहुंचती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में जीविका दीदियों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासिय विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए ड्रेस की सिलाई कर न सिर्फ करोड़ों का टर्नओवर खड़ा किया है, बल्कि अपनी हुनर और शिल्पकारी के माध्यम से लाखों बच्चों के लिए आकर्षक ड्रेस उपलब्ध कराने के सपने को साकार किया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार के ग्रामीण समाज में बदलाव की कहानी अब केवल सरकारी योजनाओं, आंकड़ों और घोषणाओं से नहीं लिखी जा रही है, बल्कि इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण अध्याय उन महिलाओं के हाथों लिखा जा रहा है, जिन्हें लंबे समय तक घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित समझा जाता रहा। जीविका से जुड़ी महिलाओं का सिलाई के काम के जरिये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना इसी परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। सिलाई मशीन की आवाज अक्सर घर के किसी छोटे कमरे तक सीमित समझी जाती रही है।

सम्पादकीय



कारोबार का आंकड़ा नहीं, बल्कि यह बताने वाला संकेतक है कि सरकारी मांग किस तरह ग्रामीण क्रयशक्ति को मजबूत कर सकती है। इस पहल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं की आर्थिक पहचान में बदलाव है। ग्रामीण महिला के लिए नियमित आय का अर्थ केवल घर की आमदनी में कुछ रुपये जोड़ देना नहीं है। जब महिला स्वयं कमाती है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ती है, भुगतान प्राप्त करती है, उत्पादन की योजना समझती है और सामूहिक कारोबार में निर्णय लेती है, तब उसके सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता धीरे-धीरे घरेलू निर्णयों में भागीदारी, वित्तीय समझ और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। यही कारण है कि जीविका जैसे महिला समूहों को केवल स्वयं सहायता समूह मानना पर्याप्त नहीं होगा, वे ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं का नया आधार बन सकते हैं। हालांकि, इस उपलब्धि का मूल्यांकन केवल टर्नओवर के आधार पर नहीं होना चाहिए। 126 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावशाली है, लेकिन असली प्रश्न यह है कि इसमें से वास्तविक आय के रूप में महिलाओं तक कितना पहुंचा, प्रति महिला औसत आय कितनी बनी, भुगतान कितनी नियमितता से हुआ और उत्पादन लागत, मशीन, कच्चे माल तथा प्रशिक्षण का खर्च निकालने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में कितना स्थायी सुधार आया। इसी तरह गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति और उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी इस मॉडल की दीर्घकालिक सफलता के जरूरी पैमाने हैं। यहां सरकार के लिए एक बड़ी नीति-संभावना भी दिखायी देती है। यदि विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों की ड्रेस के बाद सरकारी खरीद के अन्य क्षेत्रों—फर्नीचर, स्कूल बैग, स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण, स्वच्छता सामग्री,

हस्तशिल्प, फर्निशिंग और सामुदायिक उपयोग की वस्तुओं में भी महिला उत्पादक समूहों को अवसर मिले, तो बिहार में सरकारी खरीद का एक नया विकेंद्रीकृत मॉडल विकसित किया जा सकता है। इससे सरकारी धन का बड़ा हिस्सा स्थानीय उत्पादन और रोजगार को प्रोत्साहित कर सकता है। लेकिन, इसके लिए केवल सरकारी ऑर्डर पर्याप्त नहीं है। महिला उत्पादक कंपनियों को पेशेवर प्रबंधन, लेखांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन, ब्रांडिंग, डिजिटल भुगतान, कांशलील पूंजी और बाजार विस्तार की क्षमता भी देनी होगी। सरकारी संरक्षण से पैदा हुआ कारोबार यदि केवल सरकारी ऑर्डरों पर निर्भर रह गया, तो उसकी स्थिरता सीमित हो सकती है। अगला लक्ष्य होना चाहिए कि जीविका से जुड़ी महिला उत्पादक कंपनियां सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनें। राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। अब उस राजनीतिक भागीदारी को आर्थिक भागीदारी से जोड़ना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व तभी व्यापक अर्थ ग्रहण करता है, जब प्रतिनिधित्व के साथ संसाधनों और आर्थिक निर्णयों तक पहुंच भी बढ़े। ग्रामीण महिला यदि पंचायत की प्रतिनिधि होने के साथ-साथ उत्पादक, उद्यमी और आय अर्जित करने वाली आर्थिक इकाई भी बनती है, तो ग्रामीण सत्ता-संरचना का चरित्र बदल सकता है। इसीलिए, जीविका दीदियों की कहानी को केवल 'महिलाओं ने ड्रेस सिकवर करोड़ों का कारोबार किया' जैसी उपलब्धि तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसके भीतर बिहार के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण चवाल छिपा है—व्याा राज्य अपनी विशाल सरकारी खरीद शक्ति को

स्थानीय रोजगार और महिला उद्यमिता के साथ स्थायी रूप से जोड़ सकता है? यदि इसका उत्तर हां है, तो जीविका की सिलाई इकाइयां एक सफल परियोजना से आगे बढ़कर नीति का मॉडल बन सकती हैं। 90 लाख से अधिक ड्रेस और 126 करोड़ रुपये का टर्नओवर शुरूआत के लिए उत्साहजनक आंकड़े हैं। असली उपलब्धि तब होगी जब इन आंकड़ों के पीछे खड़ी हजारों महिलाओं की आय स्थायी हो, उनका कारोबार बाजार में टिकाऊ हो और उनके आर्थिक फैसलों में उनकी आवाज निर्णायक हो। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जीविका दीदियां केवल अपने परिवार का सहारा न रहकर बिहार के प्रगति की रीढ़ भी बन चुकी हैं। जब एक गांव की महिला अपने हुनर से आत्मनिर्भर बनती है, तो वह न केवल अपने बच्चों के सपनों को पंख देती है, बल्कि पूरे समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर देती है। अब जरूरी है कि इस मॉडल को आंकड़ों से आगे ले जाकर स्थायी आर्थिक संरचना को पेशेवर प्रबंधन, लेखांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन, ब्रांडिंग, डिजिटल भुगतान, कांशलील पूंजी और बाजार विस्तार की क्षमता भी देनी होगी। सरकारी संरक्षण से पैदा हुआ कारोबार यदि केवल सरकारी ऑर्डरों पर निर्भर रह गया, तो उसकी स्थिरता सीमित हो सकती है। अगला लक्ष्य होना चाहिए कि जीविका से जुड़ी महिला उत्पादक कंपनियां सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनें। राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। अब उस राजनीतिक भागीदारी को आर्थिक भागीदारी से जोड़ना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व तभी व्यापक अर्थ ग्रहण करता है, जब प्रतिनिधित्व के साथ संसाधनों और आर्थिक निर्णयों तक पहुंच भी बढ़े। ग्रामीण महिला यदि पंचायत की प्रतिनिधि होने के साथ-साथ उत्पादक, उद्यमी और आय अर्जित करने वाली आर्थिक इकाई भी बनती है, तो ग्रामीण सत्ता-संरचना का चरित्र बदल सकता है। इसीलिए, जीविका दीदियों की कहानी को केवल 'महिलाओं ने ड्रेस सिकवर करोड़ों का कारोबार किया' जैसी उपलब्धि तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसके भीतर बिहार के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण चवाल छिपा है—व्याा राज्य अपनी विशाल सरकारी खरीद शक्ति को

स्थानीय रोजगार और महिला उद्यमिता के साथ स्थायी रूप से जोड़ सकता है? यदि इसका उत्तर हां है, तो जीविका की सिलाई इकाइयां एक सफल परियोजना से आगे बढ़कर नीति का मॉडल बन सकती हैं। 90 लाख से अधिक ड्रेस और 126 करोड़ रुपये का टर्नओवर शुरूआत के लिए उत्साहजनक आंकड़े हैं। असली उपलब्धि तब होगी जब इन आंकड़ों के पीछे खड़ी हजारों महिलाओं की आय स्थायी हो, उनका कारोबार बाजार में टिकाऊ हो और उनके आर्थिक फैसलों में उनकी आवाज निर्णायक हो। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जीविका दीदियां केवल अपने परिवार का सहारा न रहकर बिहार के प्रगति की रीढ़ भी बन चुकी हैं। जब एक गांव की महिला अपने हुनर से आत्मनिर्भर बनती है, तो वह न केवल अपने बच्चों के सपनों को पंख देती है, बल्कि पूरे समाज का सिर गर्व से ऊंचा कर देती है। अब जरूरी है कि इस मॉडल को आंकड़ों से आगे ले जाकर स्थायी आर्थिक संरचना को पेशेवर प्रबंधन, लेखांकन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन, ब्रांडिंग, डिजिटल भुगतान, कांशलील पूंजी और बाजार विस्तार की क्षमता भी देनी होगी। सरकारी संरक्षण से पैदा हुआ कारोबार यदि केवल सरकारी ऑर्डरों पर निर्भर रह गया, तो उसकी स्थिरता सीमित हो सकती है। अगला लक्ष्य होना चाहिए कि जीविका से जुड़ी महिला उत्पादक कंपनियां सरकारी खरीद के साथ-साथ निजी बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनें। राजनीतिक दृष्टि से भी यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। बिहार में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पंचायतों और स्थानीय संस्थाओं में लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। अब उस राजनीतिक भागीदारी को आर्थिक भागीदारी से जोड़ना आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व तभी व्यापक अर्थ ग्रहण करता है, जब प्रतिनिधित्व के साथ संसाधनों और आर्थिक निर्णयों तक पहुंच भी बढ़े। ग्रामीण महिला यदि पंचायत की प्रतिनिधि होने के साथ-साथ उत्पादक, उद्यमी और आय अर्जित करने वाली आर्थिक इकाई भी बनती है, तो ग्रामीण सत्ता-संरचना का चरित्र बदल सकता है। इसीलिए, जीविका दीदियों की कहानी को केवल 'महिलाओं ने ड्रेस सिकवर करोड़ों का कारोबार किया' जैसी उपलब्धि तक सीमित करना उचित नहीं होगा। इसके भीतर बिहार के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण चवाल छिपा है—व्याा राज्य अपनी विशाल सरकारी खरीद शक्ति को

(लेखिका समाजसंघिका और स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

देशज ज्ञान में छिपा आपदा से बचाव का रास्ता

वीरेंद्र कुमार पेन्सूली

हम हिमालय या अन्यत्र भी प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपभोग या अपव्यय कर रहे हैं, उतना प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हो रहा है। जैव विविधता के मामले में उपभोग या पर्यावरणीय आघातों से जो जैविक जातियां-प्रजातियां संकट में पहुंच गयी हैं या समाप्त हो गयी हैं, उनकी भरपाई नहीं हो रही है। यह ईकोसिस्टम सेवा क्षमताओं व प्रवाहों पर प्रतिकूल असर डालता है। कई राणनीतियों या चल रहे कार्यक्रमों को मौसम में हो रहे बदलाव प्रभावित कर रहे हैं।
किसी आपदा के बाद जब सरकार अध्ययन कराने की बात करती है, तो वह राजनीतिक रूप से उस समस्या को टालने की प्रक्रिया होती है। जैसे तब तक बरसातें रुक जाती हैं या जंगलों में लगी आग मौसमी कारणों से बुझ जाती है। सड़कों के प्लाइनमेंट के मामले में भी ऐसा होता है। राजनेता उन क्षेत्रों में सड़क ले जाने के लिए

वोट बैंक के कारण दबाव डालते रहते हैं, जिन क्षेत्रों में सड़क ले जाने से जलस्रोतों और वनों को हानि पहुंच सकता है या न्ये भूखलन क्षेत्र बन सकते हैं। नदी से दूर निर्माण करने के सुझाव ही नहीं माने जाते हैं। इसके लिए तो राजनीतिज्ञ इस हद तक जा सकते हैं कि वे उन सभी दलीलों को जुटा देते हैं, जिनसे बुग्यालों को बुग्याल मानने से ही इनकार कर दिया जाए। नदियों की चौड़ाई पर ही सर्वालिंया निशान लगा देते हैं। बांध जलाशय बन गये तो उनमें मनमाने स्तर तक पानी भरवाने में गुरेज नहीं करते या उस तथ्य की अन्देखी कर देते हैं। इस समय दस राष्ट्रो और लगभग 1.90 अरब लोगों को हिमालय से सेवाएँ मिलती हैं। स्थानीय लोगों के ईकोसिस्टम संबंधी ज्ञान का लाभ नहीं लिया जा रहा है। यदि स्थानीय समुदाय को काम दिया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो तो ईकोसिस्टम के पुनर्वास की कीमत कम हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी से होने वाले नुकसान कम किये जा सकते हैं और अभियंकी व पारिस्थितिकी, दोनों को मदद मिल सकती है। पारंपरिक बीज संरक्षण की जानकारी स्थानीय समुदाय आपको दे सकता है। यह



पहाड़ी खेतों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक सहनशीलता और अनुकूलन क्षमता ला सकता है।

आपदाओं के बीच बचे रहने के लिए स्थानीय स्तर के ज्ञान, तकनीकों व अनुभवों का डॉक्यूमेंटेशन और सामूहिक उपयोग करने से अभियंकी व स्थानीय समुदायों में ज्ञान-कौशल की कुछ विशिष्टताएँ भी पनप सकती हैं। बाहरी जगत से संपर्कों के अभाव में दुर्गम क्षेत्रों में अपनी

सुरक्षा व रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें आविष्कार व नवाचार करने ही पड़ते हैं। दुरुह, दुर्गम पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए पीढ़ियों व सदियों से वहां विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के लिए स्थानीय स्तर पर काम के तौर-तरीकों, औजारों व ज्ञान को विकसित करना और सहजना आवश्यक रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं, जब भूकम्पों में भी पीढ़ियों पुराने पहाड़ी मकान या अन्न भंडारण

संरचनाएं बची रह जाती हैं। या सुखा, अकाल या अन्य मौसम की मारों के बीच भी स्थानीय लोग पहाड़ों के खेतों व जंगलों में कुछ ऐसा पैदा हुआ पहचान लेते हैं, जिसे स्थानीय निवासी बचे रहने के लिए खा सकते हैं। पहाड़ी आपदाओं से बचाव व राहत में इनसे मदद मिल सकती है। इस तरह का देशज ज्ञान स्थानीय स्तर पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी झेली जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भों व अनुभवों से ही उपजता है। इसे पिछली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देती हैं। अब ऐसे ज्ञान की थाती की निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। पहाड़ों से भारी मात्रा में पलायन भी इसका एक कारण है। बाजारी व्यवस्थाओं से ही जरूरतों के पूरा होने तथा कई प्रकार के प्रतिबंधों के कारण प्राकृतिक क्षेत्रों व संसाधनों से लोगों का दुराव होने के कारण भी पर्वतीय समुदाय के प्रकृति को समझने के अवसरों में कमी आयी है। इससे प्रासंगिक आपदा प्रबंधन के देशज ज्ञान की थाती भी सिमटी है।

भूभर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालयी पहाड़ संवेदनशील संतुलन में हैं। यहां आपदाओं से सहज प्रभावित होने वाली संरचनाएं हैं। भू-

उपयोग परिवर्तन भूपारिस्थितिकी, भू-संस्कृति और लोगों की मांगों व पसंद में भी अंतर ला रहा है। स्थानीय लोग जब बाहर की चीजें मांगेंगे तो निर्भरता बढ़ेगी। जब बादल फटता है या भीषण बरसात आती है, तो सड़कों की मोड़दार, तेज ढालों से पानी के बहाव और उसकी शक्ति में अप्रत्याशित तेजी आती है। इससे नीचे के मकानों, खेतों, मैदानों और सूखे नालों में बजरी, पत्थर व मलबा भारी मात्रा में आकर नुकसान कर देता है। सड़कों को पहाड़ों से काटते वक्त पहाड़ों का स्थिर प्राकृतिक ढलान बिगड़ जाता है। ये अस्थिर ढलान बादल फटने के समय लगातार भूखलन वाले क्षेत्र बन जाते हैं। हिमालयी विकास केवल विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विषय नहीं है। यह ज्ञान, अनुभव व पारंपरिकता का भी विषय है। वहां के रहने वाले अपने-अपने स्तर पर जिन तौर-तरीकों से बचे चाहते हैं, उन पर अपना विज्ञान न थोपें। जिन तरीकों से वे सफलता से बचे रह रहे हैं, हिमालय से कम-से-कम संसाधन लेते हुए उनके पीछे के विज्ञान को समझिए। तब उनके लिए मददगार वातावरण बनेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

सवालों का समाधान ही इस पीढ़ी की पीड़ा का मरहम

विश्वनाथ सचदेव

ल गभग तेरह साल पुरानी बात है। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री-पद के उम्मीदवार थे। अपनी योग्यता-क्षमता को दिखाने के लिए उनके पास गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया गया काम था। उसी दौरान उन्होंने राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज में एक भाषण दिया था।
उस भाषण में वह सब था, जो एक उम्मीदवार मतदाता को रिझाने के लिए कह सकता है। सपना दिखाया गया था, वादे किये गये थे। उस भाषण का एक जुमला बहुत चर्चित हुआ था तब-आधे भरे और आधे खाली गिलास वाला मुहावरा। आशावाद और निराशावाद का अंतर समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण दिया जाता है और कहा जाता है कि वह आशावादी है, जो गिलास को आधा भरा हुआ बताता है और जो कहता है कि गिलास आधा खाली है, वह निराशावादी है। तब नरेंद्र मोदी ने इस मुहावरे में एक बात और जोड़ी थी, जिसने इस घिसी-पिटी बात को 'ताजगी' दे दी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'मुझे गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है—आधा पानी से, और आधा हवा से।'
तेरह साल बाद नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली के उसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में छात्रों के, और इसके बहाने देश को, संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अक्सर कॉलेज के शताब्दी

समारोह का था और जो विद्यार्थी उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, वे तब शायद किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। जिन्होंने तेरह साल पहले वाला 'पूरे भरे गिलास' वाला भाषण सुना था, उन्हें वह याद भी था और मेरी तरह शायद वे यह उम्मीद भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे भरे गिलास वाली अपनी बात दोहरायेंगे। और प्रधानमंत्री ने भी अपनी कही उस बात को दोहराना जरूरी समझा। सामने बैठे विद्यार्थियों के लिए यह बात नयी थी। उन्हें भी प्रधानमंत्री का आशावाद अच्छा लगा। तब भावी प्रधानमंत्री ने सपने दिखाये थे, अब वर्तमान प्रधानमंत्री 'अपना रिपोर्ट कार्ड' लेकर उपस्थित थे। पिछले तेरह साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार की उपलब्धियों को गिनना शायद स्वाभाविक था। खूब गिनायीं, और तालियां भी बजीं।

प्रधानमंत्री यह जानते थे कि कॉलेज में पढ़ने वाली जिस पीढ़ी को वे संबोधित कर रहे हैं, वह 'जेन जी' नये मुहावरों को समझती है। देश के युवकों की एक अपनी भाषा है, अपना मुहावरा है उनका। प्रधानमंत्री ने कोशिश की उनसे उनकी भाषा में बात करने की। यह पीढ़ी सपने देखने के बजाय ठोस उपलब्धियों की जानकारी चाहती है। उपलब्धियां गिनायीं उन्होंने। पर यह 'जेन जी' सवाल उठाने वाली है। उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए, पर ऐसे मोटे आत्मन्योषण के भी होते हैं। यह अक्सर एक प्रसिद्ध शिक्षा-संस्थान की शताब्दी का था। विद्यार्थी उस



शिक्षा-स्थिति के बारे में भी सुनना चाहते थे, जो आज के भारत की चिंता का विषय होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले लगभग अस्सी साल में देश में अनेक महत्वपूर्ण शिक्षा-संस्थान खुले हैं। एक लंबी-चौड़ी सूची है हमारे पास नये-नये आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की। लेकिन यह सवाल भी उठता रहा है कि हमारे शिक्षा-संस्थानों को वैश्विक स्वीकार्यता क्यों नहीं मिल पायी। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर शिक्षा के उच्चतम पायदान पर दी जा रही शिक्षा आज सवालों के घेरें में क्यों है? गुणवत्ता और बुनियादी शिक्षा के स्तर पर बनी चुनौतियों को हम कब देखेंगे—स्वीकारेंगे?

लगभग 17 साल पहले हमने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अधिकार को स्वीकारा था। सर्वशिक्षा

अभियान जैसी पहल से स्थिति में कुछ सुधार आया है। पर प्राथमिक शिक्षा में जितना और जैसा सुधार अपेक्षित था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आये दिन सरकारी स्कूलों के बंद होने और निजी स्कूलों के खुलने के समाचार मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की स्थिति को लेकर पिछले कुछ दिनों में देश में देरों सवाल उठे हैं। एक-एक कमरे में चार-चार कक्षाएं एक साथ लग रही हैं। स्कूलों में टाट-पट्टी और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाओं का भी अभाव है। 'असर' जैसी संस्थाएं बार-बार इस स्थिति को उजागर कर रही हैं कि पांचवीं में पढ़ने वाला बच्चा तीसरी कक्षा की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, उसकी स्थिति भी कुल मिलाकर निराशाजनक ही है। हमारे

इंजीनियरिंग कॉलेजों की पढ़ाई भी उस स्तर की नहीं है कि डिग्री प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी रोजगार की अपेक्षाओं की शर्तों पर खरा उतर सके। उच्च शिक्षा के लिए हमारे विद्यार्थी विदेशों में जाने को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में 'स्पेस सेंटर' बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं, पर धरती पर दुर्दशा की हकीकत की गंभीरता को कब समझा जायेगा? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अपने चर्चित भाषण में प्रधानमंत्री ने नयी पीढ़ी से जुड़ने का प्रयास अवश्य किया है, पर पूरे भाषण पर चुनावी-साया दिखायी दे रहा है। यह अक्सर एक प्रसिद्ध कॉलेज की शताब्दी का था और संयोग से उस दिन शिक्षक-दिवस भी था। यही नहीं, कुछ ही अरसा पहले देश ने 'जेन जी' का असंतोष देखा था और इसी बीच ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की दुर्दशा का मसला भी उभर कर सामने आया है। ऐसे में यह अपेक्षा तो होनी ही चाहिए थी कि प्रधानमंत्री देश में शिक्षा की स्थिति और समस्या पर कुछ कहेंगे। पर इस संदर्भ में कुछ विशेष नहीं कहा उन्होंने। देश की जनता के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना भी जरूरी होता है, पर यह कदाई जरूरी नहीं है कि हमारे राजनेता चुनावी माहौल से उबर ही न सके। उबरना चाहिए उन्हें। भाषणों में जुमले और मुहावरे अच्छे लगते हैं, पर हमेशा नहीं। शिक्षा-जनत से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने हवा से भरे हुए गिलास और 'दिमागी नक्सल' वाली अपनी बातों की दोहराना जरूरी समझा, यह उनका विशेषाधिकार है।

युवा पीढ़ी से जुड़ने को उनकी अपनी कोशिश में भी कुछ गलत नहीं है, बल्कि जरूरी है इस पीढ़ी से जुड़ना, उसकी आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना। पर 'नाराज फूफ' जैसे जुमले ऐसी कोशिशों को हल्का ही बनाते हैं। हमारे समय और समाज की आवश्यकता है कि नयी पीढ़ी को समझने की ईमानदार कोशिश हो। राजनीतिक नफ़े-नुकसान से ऊपर उठकर इस पीढ़ी को समझना होगा। उसकी पीड़ा और उसकी नाराजगी भी ही हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह निराश है तो उसकी निराशा को समझने की कोशिश होनी चाहिए। बीबीसी ने श्रीराम कॉलेज के कार्यक्रम के बाद कुछ युवाओं से बातचीत की थी। उनमें एक युवक वह भी था, जिसे इसलिए कार्यक्रम में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वह काली कमीज पहने हुए था! उसने बीबीसी के संवाददाता को बताया कि शायद आयोजकों को लगा था कि काली कमीज खतरे की घंटी है। मान लेना चाहिए कि उस युवक का कोई गलत इरादा नहीं था। उसका काली कमीज पहनकर आना एक संयोग हो सकता है। वह तब यह है कि देश की जेन-जी अथवा जेन-अल्फा के पास कुछ सवाल हैं, जो उसे परेशान करते हैं। हमारे नेतृत्व को उनकी परेशानी को समझना होगा। तभी गिलास सही अर्थों में भरेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

विकास वार्ता (दैनिक) ई-पेपर प्रकाशक एवं संपादक : राजकिशोर सिंह, विकास विद्यालय शिक्षकनगर डुमरी बेगूसराय बिहार 85117, मुद्रक: सोमेश कुमार चौधरी, दामोदरपुर पासोपुर बेगूसराय बिहार -

851112, मुद्रणालय - जागो गांव, जागो प्राइवेट आईटीआई, दामादरपुर बेगूसराय-851112, RNI NO-BHHin/5/A044

एक नजर

शेफाली को उम्मीद, सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेगा भारतीय मिडिल-ऑर्डर

दुबई, एजेंसी। भारतीय टीम गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ विमेंस एशिया कप 2026 का सेमीफाइनल मैच खेलेगी। भारत के मिडिल-ऑर्डर ने इस टूर्नामेंट में फैस को निराश किया है, लेकिन, ओपनर शेफाली वर्मा ने नॉकआउट मैच से पहले उनका समर्थन किया। शेफाली का मानना है कि रन न बन पाना बस एक अस्थायी दौर है।

विमेंस एशिया कप 2026 में शेफाली और उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने भारत के लिए ज्यादातर रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली है, जबकि बाकी बल्लेबाजों को लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा। टूर्नामेंट की शुरुआत में थाईलैंड के खिलाफ 46 रन पर 8 विकेट गिरेने से टीम की मिडिल-ऑर्डर बैटिंग की समस्याएं फिर से उजागर हुईं, लेकिन शेफाली को साथी बल्लेबाजों पर नॉकआउट स्टेज ने अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेफाली वर्मा ने पत्रकारों से कहा, कभी-कभी बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन वे सभी बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं। वे सभी बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं। अगर भारती और ऋचा की बात करें, तो वे बहुत अच्छी फिनिशर हैं और मिडिल-ऑर्डर में भी बढ़िया काम करती हैं। इसलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी टीम के लिए अच्छा करेंगी। भारत ने रिकॉर्ड सात बार विमेंस एशिया कप का खिताब जीता है। इस संस्करण में 5 सितंबर को पाकिस्तान को 7 विकेट से रैंदेंदे के बाद टीम सेमीफाइनल में पहुंच रही



है। शेफाली का मानना ? है कि यह ब्रेक टीम के लिए सही समय पर मिला, ताकि वे तोरताजा हो सकें और अपनी योजनाओं को बेहतर बना सकें। उन्होंने कहा, हमारी तैयारी अच्छी रही। हमें चार दिन का ब्रेक मिला और उन दिनों में हमने अच्छी तरह रिकवर किया और प्रैक्टिस भी की। इसलिए, हम सभी सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। शेफाली वर्मा एशिया कप 2026 के तीन मुकाबलों में 104 रन बना चुकी हैं, लेकिन वह पिछले प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय हर नए मैच को एक नई शुरुआत मानती हैं। उन्होंने कहा, रबतौर बल्लेबाज जब भी मैदान पर जाती हूं, तो जीरो से शुरुआत करती हूं, लेकिन उस पारी से आत्मविश्वास मिला है। इसलिए, मैं उस आत्मविश्वास को साथ लेकर फिर से जीरो से शुरुआत करूंगी। शेफाली ने कहा कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की धीमी और स्पिन-फ्रेंडली पिचें भारत की पिचों जैसी ही हैं, जिससे टीम को ढलने के लिए एक जाना-पहचाना माहौल मिलाता है।

कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मिलेगी रफ्तार, दो महीने में रिपोर्ट होगी तैयार

नई दिल्ली, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश में विमानन अवसरंचना विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है और बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है।

इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना की टेक्नी-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दो महीने के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना के लिए योग्य सलाहकार की नियुक्ति कर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि

यदि रिपोर्ट तय समय में तैयार हो जाती है, तो एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से परियोजना की लागत का यथार्थपरक आकलन करने का भी आग्रह किया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे हेलीपोर्ट नेटवर्क का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए दूरदराज के इलाकों तक बेहतर पहुंच और आपातकालीन सेवाओं के लिए हेलीपोर्ट बेहद जरूरी हैं।

उन्होंने हेलीपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने शिमला को नियमित हवाई संपर्क उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही एयरपोर्ट की रनवे क्षमता के अनुरूप उपयुक्त विमानों के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

एलेना ने किनवेन को हराकर नंबर 1 रैंक और सेमीफाइनल में जगह बनाई

यूएस ओपन

न्यूयॉर्क, एजेंसी। एलेना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में किनवेन झेंग को हराकर यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही रायबाकिना दुनिया की नई नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। 14 सितंबर को डब्ल्यूटीए द्वारा जारी होने वाली रैंकिंग में वह नंबर वन खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएंगी।

एलेना रायबाकिना ने किनवेन झेंग को 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। रायबाकिना को झेंग ने कड़ी टक्कर दी। आर्थर एश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुरुआती सेट में रायबाकिना को धूप, परछाई और झेंग के दमदार शॉट्स से जूझना पड़ा। झेंग ने इसका फायदा उठाया और शुरुआती सेट का एकमात्र ब्रेक हासिल किया, फिर 6-3 से



सर्व किया। दूसरे सेट में मैच जल्दी बदल गया, रयबाकिना ने सर्व और बेसलाइन से अपनी लय पकड़ ली। उन्होंने 38 मिनट में 6-1 से सेट अपने नाम कर लिया और निर्णायक सेट में जगह बना ली। तीसरा सेट तब तक कड़ा रहा जब तक झेंग ने डबल-फॉल्ट करके रयबाकिना को 5-4 की बढ़त नहीं दिला दी। फिर

रयबाकिना ने वापसी करने के लिए मैच सर्व किया और सेट 6-4 से जीता। मैच के बाद रायबाकिना ने कहा, अभी यह सिर्फ एक नंबर है। बेशक, मैं सेमीफाइनल में हूं। मेरा लक्ष्य उन टूर्नामेंट्स को जीतना है जिनमें मैंने खेला है। यह एक कमाल की कामयाबी है लेकिन हम जानते हैं कि मैच के दौरान टेनिस में

यूएस ओपन: अलेक्जेंडर ज्वेरेव सेमीफाइनल में पहुंचे, करेन खाचानोव से होगा मुकाबला

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव का यूएस ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी है। जर्मनी के इस खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बोटिक वैन डे जैंडशुल्प को 6-2, 7-5, 6-1 से हराकर एकल वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अपने शुरुआती 2 मैचों को पांच-पांच सेट तक खींचने वाले ज्वेरेव ने लय पकड़ ली है और लगातार तीन मैच सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

ज्वेरेव ने शुरुआती सेट में दो बार सर्विस तोड़ी और डचमैन बोटिक को कभी भी सेटल नहीं होने दिया। दूसरे सेट में थोड़ी देर के लिए मुकाबले की झलक मिली। जैंडशुल्प ने 5-4 से आगे रहते हुए एक सेट पॉइंट हासिल किया, लेकिन ज्वेरेव के मजबूत रहने के कारण वह इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसके बाद जर्मन खिलाड़ी ने अगले गेम में सर्विस करने से पहले ब्रेक लिया, जिससे उनके विरोधी की वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं। जर्मन खिलाड़ी ने अपने सामने आए



दोनों ब्रेक पॉइंट बचाए और आठ एस के साथ मैच खत्म किया। इस जीत के साथ ही 2026 में ज्वेरेव सभी चार मेजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले और अकेले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ज्वेरेव ने इस साल का फ्रेंच ओपन जीता है, विंबलडन में उपविजेता रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में उन्हें कार्लोस अल्काराज से हार का सामना करना पड़ा था। जानिक सिनर की गैरमौजूदगी और कार्लोस अल्काराज के क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद

ज्वेरेव के पास अपना पहला यूएस ओपन खिताब और साल का दूसरा खिताब जीतने का मौका है। यूएस ओपन 2026 के सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला कैरेन खाचानोव के साथ होगा। रूस के करेन खाचानोव का क्वार्टर फाइनल मुकाबला बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स के साथ हुआ। ब्लॉक्स मुकाबले में 6-2, 7-5, 3-2 से पीछे चल रहे थे। इंजरी की वजह से उन्हें मुकाबले से बाहर होना पड़ा और खाचानोव ने सेमीफाइनल में जगह बना ली।

एप्पल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ 2.99 लाख रुपए की कीमत पर भारत में हुआ लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने 'आईफोन डुओ' लॉन्च करके फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर दी और भारत में इसकी कीमत 2,99,900 रुपए निर्धारित की गई है। इसके जरिए कंपनी का मकसद अपने प्रीमियम आईफोन इकोसिस्टम के साथ बड़ी डिस्स्ले देना और ऐसे यूजर्स को आकर्षित करना है जो कंटेंट देखने, मल्टीटास्किंग करने और कुछ नया बनाने के लिए नए तरीके तलाश रहे हैं। 23 अक्टूबर से उपलब्ध होने वाले इस डिवाइस में 7.6-इंच की इनर डिस्स्ले और 5.4-इंच की आउटर डिस्स्ले दी गई है। इसके अलावा, दोनों स्क्रीन का आस्पेक्ट रेश्यो एक जैसा है, जिससे कंटेंट को दोनों के बीच सही अनुपात



में एडजस्ट किया जा सकता है।

कंपनी के अनुसार, अंदर वाली डिस्स्ले में नैनो-टेक्सचर फिनिश है, जो चमक को कम करती है और क्रीज को कम दिखने देती है। साथ ही, आईफोन डुओ में एप्पल की ए20 प्रो चिप लगी है और इसमें एडवांस्ड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, डुअल-बैटरी आकिंटिक्कर और नया कैमरा सिस्टम भी शामिल है।

हालांकि, कंपनी का दावा है कि इनर डिस्स्ले पर 31 घंटे तक और आउटर डिस्स्ले पर 44 घंटे तक वीडियो प्लेबैक किया जा सकता है। इस डिवाइस में फोल्डेबल के लिए खास कैमरा अनुभव भी दिए गए हैं, जैसे स्मार्ट टेक, डुओ प्रीव्यू और डुओ फेसटाइम। वहीं, आईओएस 27 में स्प्लिट व्यू और ऐप्स के पेयर को सेव करने जैसे मल्टीटास्किंग फीचर्स

जोड़े गए हैं।

एप्पल के सीओओ जॉन टर्नर्स ने कहा, आईफोन डुओ, ओरिजिनल आईफोन के बाद से आईफोन में सबसे बड़ा बदलाव है। पूरी तरह से नए डिजाइन और आसान अनुभव के साथ, यह दिखाता है कि जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ बनाया जाता है तो क्या-क्या मुमकिन है। साथ ही, यह फोल्डेबल फोन के इस्तेमाल के तरीके को भी नए सिरे से परिभाषित करता है। साइबरमीडिया रिसर्च (सीएमआर) के इंडस्ट्री इंटीलिजेंस ग्रुप के प्रमुख प्रभु राम ने कहा कि इस डिवाइस से शॉर्ट-टर्म में ज्यादा बिक्री होने के बजाय, प्रो सीरीज से ऊपर एक 'अल्ट्रा-प्रीमियम' कैटेगरी बनने की संभावना है।

कोको गॉफ ने मीरा एंड्रीवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

यूएस ओपन

न्यूयॉर्क, एजेंसी। कोको गॉफ ने क्वार्टर फाइनल में मीरा एंड्रीवा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गॉफ ने मीरा एंड्रीवा को 2-6, 7-6, 6-2 से हराया। गॉफ 2023 के बाद पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। गॉफ मैच की शुरुआत में कमजोर दिख रही थीं और एंड्रीवा को टक्कर नहीं दे पा रही थीं। एंड्रीवा ने मात्र 26 मिनट में पहला सेट 6-2 से जीता। पहले सेट के बाद ऐसा लग रहा था कि एंड्रीवा सेमीफाइनल में जगह बना लेंगी, लेकिन यहीं से अनुभवी गॉफ ने वापसी की।

दूसरा सेट शुरू होते ही मोमेंटम बहुत बदल गया। एंड्रीवा का स्तर गिर गया। उन्होंने गलतियां करना शुरू कर दिया जिससे गॉफ को मुकाबले में वापस आने का मौका

मिल गया। इसके बाद दो खिलाड़ियों के बीच एक तनाव वाला संघर्ष शुरू हुआ। कोई भी रेली करने को तैयार नहीं था या कर नहीं पा रहा था, जब तक कि दूसरा जोर न डाले।

आखिरकार सेट टाईब्रेक में गया, जहां गॉफ ने खुद को दो बार मैच पॉइंट पर पाया। एंड्रीवा के पहला मूव करने का इंतजार करने के बजाय, गॉफ ने आक्रामक तरीका अपनाया। एंड्रीवा किसी भी मौके को भुनाने में नाकाम रही। उन्होंने पहले मैच-पॉइंट लॉब को बेसलाइन के पार भेज दिया और फिर दूसरे पर एक और गलती की, जिससे गॉफ को टिके रहने का मौका मिल गया। यही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गॉफ ने अचानक एक और गिगर पाया जबकि एंड्रीवा का आत्मविश्वास कम होने लगा। एंड्रीवा इस गिरावट से उबर नहीं पाईं। तीसरा सेट गॉफ ने 6-2 से जीतकर गॉफ ने मैच अपने नाम किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।

सीपीएल 2026 : 47 साल के इमरान ताहिर का ऐतिहासिक 'पंच'



घातक गेंदबाजी की वजह से सेंट लूसिया क्रिंस 18.5 ओवर में 119 रन पर सिमट गई। कामिल पूरन ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि ओबस पिएनार ने 35 रन बनाए। इमरान के अलावा, अमेजन के लिए मेहदी हसन मिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की। मिराज ने 3 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। डूवेन प्रिटोरियस और रोमारियो शेफर्ड को 1-1 विकेट मिला। 120 रन का लक्ष्य अमेजन वॉरियर्स ने 18.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन बनाकर हासिल कर लिया और मैच 4

विकेट से जीता। पारी की शुरुआत करने आए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 37 रन बनाए। 40 गेंदों की अपनी पारी ने फिलिप्स ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। क्वेंटिन सैम्पसन ने 11 गेंदों पर 5 छक्कों और 1 चौके की मदद से 37 रन का नाबाद पारी खेली। विकेटकीपर शाई होप ने 21 और शिमरोन हिटमार्शर ने 14 रन बनाए। सेंट लूसिया के लिए कप्तान रोस्टन चेज ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट लिए। मैथ्यू फोर्ड, महिश थिक्काणा और चरिथ असलांका को 1-1 विकेट मिला।

केंद्र ने जीएसटी ग्रा्थ अनुमानों की आलोचना को खारिज किया

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने जीएसटी रेवेन्यू ग्रा्थ के अपने हिसाब-किताब की आलोचना को खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि तुलना एक जैसे आधार पर की जानी चाहिए, न कि अलग-अलग टैक्स बेस के बीच। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हर महीने जारी होने वाले जीएसटी रेवेन्यू के आंकड़े पूरी जानकारी के साथ जीएसटी रेवेन्यू परफॉर्मंस की सही तस्वीर दिखाते हैं। सीबीआईसी के बयान में कहा गया है कि जीएसटी कार्डसिल ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर 22 सितंबर, 2025 से कंपनसेशन सेस को बंद करने का फैसला किया था। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर सेस भी 1 फरवरी,

2026 से हटा दिया गया था। इसलिए, इस अवधि के लिए कोई सेस कलेक्शन नहीं हुआ। इसे देखते हुए, नवंबर 2025 (जीएसटी रेट में बदलाव के बाद पहला टैक्स पीरियड) से, पॉजिटव डोमेन में जारी जीएसटी रेवेन्यू के आंकड़ों में कंपनसेशन सेस को नीचे एक टैबल में अलग से दिखाया गया था, और साल-दर-साल ग्रा्थ की गणना संबंधित अवधियों के लिए सीजीएसटी, एसेजीएसटी और आईजीएसटी वाले टैक्स बेस पर की गई थी। बयान में कहा गया है कि पूरी जानकारी देने के लिए एक फुटनोट भी शामिल किया गया था। सीबीआईसी ने कहा, ग्रा्थ रेट तथा सार्थक होती है जब उसकी गणना तुलना करने लायक आधार पर की जाए, यानी तुलना के दोनों तरफ एक ही तरह के लेवी (टैक्स) हों।

सड़कों से आगे बढ़े मोनेटाइजेशन, रेल और शहरी इंफ्रा में प्राइवेट पूंजी लाना जरूरी: एनसीईईआर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत को रेल, शहरी और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट पूंजी लाने के लिए मोनेटाइजेशन मॉडल की जरूरत है। यह बात एनसीईईआर के डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल ने कही।

नई दिल्ली में सीआईआई के सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 'रिवोलुशंसिंग प्राइवेट कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट' में सुरेश गोयल ने कहा कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी को सड़कों से आगे बढ़ने की जरूरत है। रेलवे, स्ट्रेटिजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी कनेक्टिविटी में प्राइवेट कैपिटल लाने के लिए पीपीपी मॉड और कंसेशन प्रेमवर्क जैसे नए मॉडल की जरूरत है। गोयल ने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक स्ट्रेटिजिक मोड़ पर हैं। सड़क सेक्टर के मोनेटाइजेशन ने दिखाया है कि अच्छी तरह से तैयार कंसेशन

प्रेमवर्क निवेशकों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन इस मॉडल को एक्स सेक्टर में अभी तक सफलतापूर्वक नहीं अपनाया गया है। उन्होंने एनएचआई के कंसेशन प्रेमवर्क का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हाईवे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जोखिम प्रतिस्पर्धी रूट के आने से रेवेन्यू कम होना है। इसके लिए मौजूदा प्रेमवर्क में टारगेट रेवेन्यू तय किया जाता है। अगर वास्तविक रेवेन्यू कम रहता है तो कंसेशन अवधि बढ़ा दी जाती है और ज्यादा होने पर अवधि घटा दी जाती है। इस मॉडल को रेलोबल निवेशकों ने अपनाया है और इसने एनएचआई एसेट्स के मोनेटाइजेशन में काफी मदद की है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती इस सफल प्रेमवर्क को रेलवे और अन्य सेक्टर में लागू करने की है। समिट में नीति आयोग में पीपीपी प्रोग्राम डायरेक्टर पार्थ सारथी रंथुी ने

कहा कि पीपीपी इकोसिस्टम हाईवे, पोर्ट और एविएशन से आगे बढ़कर रेलवे, हेल्थकेयर, सॉलरिड वेस्ट और वॉटरवेज जैसे क्षेत्रों में फैल रहा है। हर एसेट की विशेषता और रिस्क प्रोफाइल के आधार पर सही पीपीपी मॉडल तय करना होगा। सीआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर कार्डसिल के चेयरमैन बीबीएन राव ने कहा कि पिछले तीन दशकों से पीपीपी का मतलब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप है, लेकिन भाविष्य के लिए इसका मतलब बढ़ता, धैर्य और लगन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देरी वाला प्रोजेक्ट सिर्फ देरी वाली संपत्ति नहीं, बल्कि कमी हुई नौकरियां और धीमी प्रगति है। अगर प्राइवेट कैपिटल चाहिए तो प्रोजेक्ट को पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना आईडिया सोचना। सीआईआई की पीपीपी पर नेशनल कमिटी के चेयरमैन विनायक चटर्जी ने दो बड़ी रुकावटें गिनाईं।



सर्वांगासन-हलासन के बाद क्यों जरूरी है मत्स्यासन



नई दिल्ली, एजेंसी। योग में हर आसन का अपना महत्व होता है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब आसन को सही क्रम और संतुलन के साथ किया जाए। सर्वांगासन और हलासन योग के महत्वपूर्ण आसनों में गिना जाता है, लेकिन इन दोनों आसनों को करने के बाद शरीर में दबाव पड़ता है। इसी को ठीक करने के लिए मत्सासन को करना आवश्यक काउंटर-पोज यानी विपरीत आसन माना गया है। हम आपको बताएंगे कि सर्वांगासन और हलासन के तुरंत बाद मत्स्यासन काउंटर-पोज (विपरीत आसन) करना आवश्यक क्यों होता है।

आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार, सर्वांगासन और हलासन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए बाद में मत्सासन करना बेहद जरूरी और अनिवार्य माना गया है। जब कोई भी साधक सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करता है, तो शारीरिक बदलाव आते हैं, जिन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए मत्स्यासन एक पूरक आसन के रूप में काम करता है।

सर्वांगासन और हलासन दोनों ही 'इनवर्जन' (उल्टे होने वाले) आसन हैं, जिनमें छाती आगे की तरफ झुकती है और टुडूनी पूरी तरह से छाती से चिरक जाती है। मत्स्यासन में जब फिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाकर रीढ़ और गर्दन को पीछे मोड़ा जाता है, तो यह जालंधर बंध के दबाव को

तुरंत संतुलित कर देता है।

योग विशेषज्ञों के अनुसार, हलासन और सर्वांगासन के दौरान रीढ़ की हड्डी और गर्दन की पीछे की मांसपेशियों पर गहरा और तीव्र खिंचाव आता है। इससे गर्दन और पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियां अत्यधिक तनी हुई स्थिति में आ जाती हैं। मत्स्यासन रीढ़ को विपरीत दिशा में (पीछे की ओर) मोड़कर एक बेहतरीन काउंटर-स्ट्रेच देता है। इससे गर्दन, कंधों और रीढ़ की हड्डी की अकड़न व तनाव दूर होता है और मांसपेशियों का संतुलन वापस सामान्य हो जाता है। इन दोनों आसनों में गर्दन और गले पर गहरा दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में जकड़न आ सकती है। इसी जकड़न को खोलने और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए मत्स्यासन को आवश्यक काउंटर-पोज यानी विपरीत आसन माना गया है।

योग विज्ञान का नियम है कि यदि शरीर को एक दिशा में गहराई से मोड़ा गया है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए विपरीत दिशा में मोड़ना (काउंटर -पोज) जरूरी है। सर्वांगासन और हलासन 'फॉरवर्ड बेंडिंग' (गर्दन के लिए) हैं, तो मत्स्यासन उनका सटीक 'बैकवर्ड बेंडिंग' इलाज है जो रीढ़ व गर्दन को चोटील होने से बचाता है। हालांकि, इन तीनों आसनों को करने से पहले किसी विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें और गंभीर बीमारी, हालिया सर्जरी, प्रेग्नेंट महिलाएं वाले व्यक्ति आसनों को करने से बचें।

गर्भावस्था में एनीमिया हो तो शिशु के मस्तिष्क का आकार हो सकता है छोटा : स्टडी

लंदन, एजेंसी। गर्भावस्था के दौरान मां में एनीमिया यानी खून की कमी से जुड़ा रही है तो इसका असर शिशु के मस्तिष्क विकास पर पड़ सकता है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि एनीमिया पीड़ित माताओं से जन्मे बच्चों का कुल मस्तिष्क आयतन अन्य बच्चों की तुलना में औसतन करीब चार प्रतिशत कम होता है।

यह अध्ययन ब्रिटेन के 'किंग्स कॉलेज लंदन और दक्षिण अफ्रीका के यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन' के शोधकर्ताओं ने किया। शोधकर्ताओं ने केप टाउन में 300 से अधिक माताओं और उनके बच्चों का अध्ययन किया तथा बच्चों के मस्तिष्क की कई बार स्कैनिंग की। यह निगरानी बच्चों के करीब तीन महीने की उम्र से लेकर दो साल तक की गई। खास बात यह है कि अध्ययन में शामिल एनीमिया से पीड़ित माताओं में बीमारी का स्तर हल्का था। इसके बावजूद उनके



बच्चों के मस्तिष्क के कुल वॉल्यूम (आयतन) में अंतर देखा गया। इससे यह संकेत मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का पर्याप्त स्तर ब्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। द गार्डियन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ताओं का ध्यान केवल पूरे मस्तिष्क के आकार पर ही नहीं है। इससे पहले इसी शोध समूह के काम में गर्भावस्था के दौरान मातृ एनीमिया और बच्चों के मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण

हिस्सों, विशेष रूप से 'कॉर्पस कॉलोसम और कंडेट न्यूक्लियस', के अपेक्षाकृत छोटे आयतन के बीच संबंध सामने आया था। बाद के अध्ययन में भी ये प्रभाव बच्चों के 6-7 वर्ष की उम्र तक बने रहने के संकेत मिले। कॉर्पस कॉलोसम मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच कम्प्युनिकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि कंडेट न्यूक्लियस कई तरह की संज्ञानात्मक और मोटर प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है। हालांकि, इन निष्कर्षों का यह अर्थ नहीं है कि

पीठ की अकड़न और कब्ज से हैं परेशान सुप्त मत्स्येंद्रासन है रामबाण उपाय

नई दिल्ली, एजेंसी। दफ्तर में घंटों बैठकर काम करने और शारीरिक गतिविधि कम होने की वजह से कमर दर्द, कब्ज और पीठ में अकड़न की समस्या आम हो गई हैं। इन शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के व्यक्ति योग का सहारा ले सकता है। सही खानपान और योग से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। योग के इन्हों आसनों में 'सुप्त मत्स्येंद्रासन' बेहद लाभदायक है, जो न सिर्फ कमर दर्द और जकड़न दूर करता है बल्कि मन को शांति मिलती है। सुप्त मत्स्येंद्रासन को अंग्रेजी में सुपाइन स्पाइल टिस्ट या रिकलाईड टिक्ट कहा जाता है। यह आसन संस्कृत के तीन शब्दों से मिलकर बना है, सुप्त (लेटना), मत्स्येंद्र (पौराणिक योगी मत्स्येंद्राथ) और आसन (मुद्रा)। यह अर्ध मत्स्येंद्रासन का लेटा हुआ, पुनर्स्थापनात्मक रूप है, जो निष्क्रिय, गुरुत्वाकर्षण-सहायता प्राप्त स्थिति में रीढ़ की हड्डी के घुमाव के समान आवश्यक लाभ प्रदान करता है और इसके लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है। यह आसन योग की शास्त्रीय परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे विश्राम, स्थिरता और रीढ़ की हड्डी में हल्का तनाव



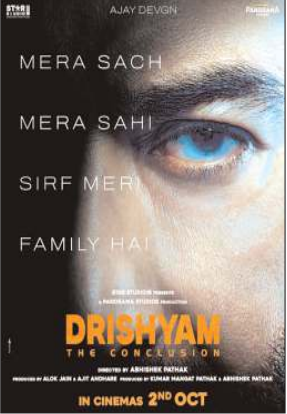
कम होता है। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने इस आसन को रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन, पीठ दर्द से राहत और पाचन तंत्र को सुधारने के लिए एक उत्कृष्ट अभ्यास माना है। सुप्त मत्स्येंद्रासन, एक लेटने की मुद्रा है जिसमें एक घुटना शरीर के आर-पार मुड़ा होता है और उसी तरफ का हाथ बाहर की ओर फैला होता है। इसे करने के दौरान रीढ़ की हड्डी कमर से गर्दन तक धीरे-धीरे घुमती है। नियमित अभ्यास से रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता बढ़ती है, कूलहों का तनाव कम होता है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है।

मनोरंजन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर रिलीज क्या इस बार बच पाएगा विजय का परिवार

मुंबई, एजेंसी। अभिनेता अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इस नए भाग में विजय सालगांवकर का सामना एक नए और मजबूत प्रतिद्वंद्वी से होगा। फिल्म में अजय देवगन विजय, तब्बू आईजी मीरा देशमुख और श्रिया सरन नंदिनी के किरदार में लौट रही हैं। इस बार जयदीप अहलावत और प्रकाश राज की एंटी हुई है, जो विजय के खिलाफ जांच की और मजबूत करते हैं।

2 मिनट 52 सेकंड के ट्रेलर में विजय सालगांवकर (अजय देवगन) एक बार फिर अपने परिवार के सीक्रेट को कानून के हाथों से बचाते नजर आएंगे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि मामला अब सिर्फ दिमागी खेल नहीं रहा बल्कि विजय और



पुलिस के बीच अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।

ट्रेलर में अजय देवगन कहते हैं, उनके बहुत ही मजबूत सबूत हैं। जयदीप अहलावत फिल्म में क्राइम ब्रांच के एसपी की भूमिका में नजर आएंगे। ट्रेलर में देखने को मिलता

है कि वे विजय सालाांवकर की समझ और चालाकी को पहचानते हैं। इसी बदलाव के बीच विजय का सामना पहले से ज्यादा खतरनाक चुनौती से होता है। ट्रेलर में प्रकाश राज का किरदार विजय के लिए कहता है, अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं। इसे मैं हल्के में लेने की कोशिश नहीं करूंगा।

ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेता अजय देवगन ने कहा कि दृश्यम 2 के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी तीसरा पार्ट भी आएगा। उन्होंने कहा, दृश्यम 2 के बाद हमें नहीं पता था कि ये फिल्म बनेगी कि नहीं क्योंकि इसे आगे बढ़ाना आसान नहीं था। इसमें कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे, जिसके दायरे में रहते हुए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाना, जहां इसे खत्म किया गया, बहुत मुश्किल था।

अभिनेता ने डायरेक्टर अभिषेक पाठक की सराहना करते हुए कहा, अभिषेक पाठक हम सभी के पास एक आइडिया लेकर आए, जिसे सभी ने खूब पसंद किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लेखन में करीब द्वाई साल काम किया था। स्क्रिप्ट वाकई काफी सराहनीय थी।

अभिनेता ने दृश्यम 3 को ही इस कहानी का अंत बताया। उन्होंने कहा, हम लोगों को यह भी लगा था कि यह स्क्रिप्ट ही इस कहानी का अंत होना चाहिए क्योंकि हर चीज को एक स्थान पर पहुंचाकर छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, फिल्म को नया रूप दिया है और कहानी को आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है कि उन्होंने शानदार काम किया है।

'एल370' के नाम पर फर्जी ऑडिशन से रहें सावधान

मुंबई, एजेंसी। मलयालम अभिनेता मोहनलाल की आगामी फिल्म 'एल370' के मेकर्स ने फर्जी ऑडिशन कॉल को लेकर लोगों को सतर्क किया। उन्होंने इस समय अपनी फिल्म के लिए किसी भी ऑडिशन या कास्टिंग की घोषणा नहीं की है। निदेशक जूड एंथनी जोसेफ ने सभी को अलर्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर एक नोट पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, रकृम्या 'एल370' के नाम से चल रहे नकली ऑडिशन पोस्टर, मैसेज या कॉल से सावधान रहें। हमने अभी 'एल370' के लिए किसी भी ऑडिशन या कास्टिंग की जरूरतों को न ही मंजूरी दी और न ही अनाउंसकिया है। कृम्या ऐसी कॉल या पोस्ट के जवाब में पर्सनल जानकारी, डॉक्यूमेंट शेयर न करें या कोई पैसे न करें। किसी भी ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट के लिए कृम्या सिर्फ हमारे वेरिफाइड और ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन चैनल पर भरोसा करें।

फिर देर हो गई... अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में मांगी माफी, ब्लॉग में बताई वजह



है, और मुश्किल समय में भी... जब आप मुश्किल पर हंसते हैं, तो 'मुश्किल' को लगता है कि वह आपको परेशान करने में नाकाम रही है... इसलिए हसिए... 'मुश्किल' खुद परेशान हो जाएगी...है ना बढ़िया... ठीक है, बहुत हो गई अपनी तारीफ... कल एक नया दिन होगा। इसके साथ ही अभिनेता ने अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पतिर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। बता दे कि कौन बनेगा करोड़पति असल ब्रिटिश फॉर्मेट हू

वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर? का आधिकारिक हिंदी वर्शन है। कंटेस्टेंट से मल्टीपल-चॉइस सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें चार संभावित विकल्पों में से सही जवाब चुनना होता है। साथ ही, अगर वे पक्का नहीं होते हैं तो वे लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेगास्टार अमिताभ बच्चन की बात करें तो, वह हाल ही में वेट्टेयन और कल्कि 289९ एडी में नजर आए थे। खबरों की मानें तो फिलहाल वो कल्कि 2 की शूटिंग में व्यस्त हैं।

राज कपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित हुए सलीम खान, पत्नी हेलेन ने जताया आभार

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान को हाल ही में प्रतिष्ठित स्वर्गीय राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। सलीम खान की दूसरी पत्नी और अभिनेत्री हेलेन ने अवॉर्ड मिलने पर उनकी तरफ से शुक्रिया अदा किया।

सलीम खान की ओर से यह सम्मान स्वीकार करने के बाद मीडिया से बात करते हुए हेलेन ने कहा कि यह अवॉर्ड दिग्गज लेखक सलीम खान के लिए एक खास पल है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अविश्वसनीय योगदान दिया है। मीडिया ने अभिनेत्री से पूछा कि इस प्रतिष्ठित सम्मान की खबर मिलने के बाद सलीम खान का क्या रिएक्शन था? हेलेन ने कहा कि उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जो उनसे प्यार करते हैं और उनका साथ देते आए हैं। हेलेन ने कहा कि वह उनकी ओर से यह सम्मान पाकर आभारी हैं। उन्होंने कहा, र मैं सलीम साहब के लिए इस अवॉर्ड के लिए आभारी हूं। उनकी सभी फिल्में मेरी पसंदीदा हैं। उनकी सेहत बहुत अच्छी है। वह बहुत मजबूत इंसान हैं और आप सभी को, पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। सलीम खान हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद स्त्रीनराइटर (पटकथा लेखक) और अभिनेता हैं, हालांकि उन्होंने बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में साइड रोल



ही किए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता की थी। इसमें बड़ा मुकाम न मिलने पर उन्होंने लेखन की तरफ रुख किया। हेलेन और सलीम खान की बात करें तो वे पहली बार 1963 की फिल्म काबली खान में प्रोफेशनली मिले थे, जिसमें हेलेन ने फीमेल लीड रोल किया था, जबकि सलीम विलेन के रोल में थे। सलीम खान और हेलन की पहली मुलाकात 1960 के दशक में फिल्मों के सेट पर हुई थी। साथ समय बिताने से उनकी यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन सलीम खान शादीशुदा था।

कश्मीर फिल्म फेस्टिवल से प्रभावित हुई एना सौरा रेमन, बोलीं- 'मैं यहां खुद फिल्म शूट करना चाहूंगी'

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मु-कश्मीर के पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश और विदेश से सिनेमा जगत की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं। स्पेन की मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर एना सौरा रेमन ने जहां कश्मीर की खूबसूरती और यहां फिल्म शूटिंग की संभावनाओं की जमकर तारीफ की, वहीं बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर रमेश सिप्पी और व्हेट्स किरण जुनेजा ने सिनेमा के जादू पर अपने विचार साझा किए। फेस्टिवल में इन सितारों की मौजूदगी ने सिनेमा को लेकर स्थानीय कलाकारों और छात्रों के उत्साह को भी बढ़ाया।

कश्मीर में अपने पहले अनुभव के बारे में बात करते हुए एना ने कहा, "मैं 8 सितंबर को ही यहां पहुंची हूं,



इसलिए मुझे यहां ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिला है। लेकिन, मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं फेस्टिवल की पूरी ऑर्गनाइजेशन और इसमें शामिल सभी लोगों से बहुत प्रभावित हूं। यहां जिस तरह से लोगों को इनवाइट किया गया है और पूरा आयोजन किया गया है, वह शानदार है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह फेस्टिवल का पहला एडिशन है, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। आमतौर पर किसी फेस्टिवल का पहला एडिशन इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए मैं यहां आकर बहुत खुश हूं और पूरी फेस्टिवल टीम को बधाई देना चाहती हूं। कश्मीर की खूबसूरती और इसे

इंटरनेशनल फिल्ममेकर्स के लिए शूटिंग लोकेशन के तौर पर प्रमोट करने की संभावना पर एना ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल का एक अहम मकसद अलग-अलग जगहों को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सामने लाना भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, "जब आप कोई फिल्म फेस्टिवल करते हैं तो उसका एक फोकस यह होना चाहिए कि देशों और शहरों को फिल्ममेकर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए खोला जाए। लोगों को इन जगहों के बारे में पता चले और यहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा काम शुरू हो। यहां के लैंडस्केप बहुत खूबसूरत हैं। पहाड़, झील और यहां की रोशनी सब कुछ फिल्म शूट करने के लिए बहुत सही है। इसलिए मुझे लगता है कि यह शूटिंग के लिए एक शानदार

जगह हो सकती है। फेस्टिवल का एक मकसद लोगों को यहां लाना और उन्हें इस जगह से रूबरू कराना भी होना चाहिए। एना ने आगे कहा, "मैं आज यहां हूं, इसलिए अब मैं कश्मीर को जानती हूं। जब भी मैं किसी पहाड़ के बारे में सोचूंगी, तो शानद मेरे दिमाग में कश्मीर की तस्वीर आएगी। और हो सकता है कि मैं भविष्य में यहां शूटिंग करने के बारे में सोचूं। फेस्टिवल से कश्मीर के स्थानीय कलाकारों और फिल्म से जुड़े छात्रों को मिलने वाले अवसरों पर भी एना ने जोर दिया। उन्होंने कहा, "ऐसे आयोजन स्थानीय युवाओं को सिनेमा के अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में सीखने और इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।